



प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान



शहरी विकास को नई रफ्तार - आधुनिक राजस्थान की नई पहचान

मजबूत सड़कें • सुगम यातायात • बेहतर ड्रेनेज • आधुनिक सीवरेंज • सुरक्षित सबवे • बेहतर मेडिकल सुविधाएं • श्रमिक कल्याण • स्वच्छ एवं हरित परिवहन

राजस्थान के शहरों को मिल रही ₹2,340 करोड़ की सौगातें 941 कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के
1 लाख 32 हजार 421 लाभार्थियों को ₹154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि की डीबीटी

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में जयपुर को बड़ी सौगात

लोकार्पण

RUHS जयपुर : 128-स्लाइस CT स्कैन मशीन

जनाना चिकित्सालय, चांदपोल : नवीन आईपीडी टावर

SMS अस्पताल :

आयुष्मान टावर अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

RUHS जयपुर :

1.5 टेस्ला MRI मशीन तथा नवीन स्नातक छात्रावास

जयपुर जिले में झोटवाड़ा के अभयपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वा. केन्द्र, रेहलाना का निर्माण कार्य

शिलान्यास

जयपुर जिले के झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय

पीएम ई-बस योजना

71 ई-बसों का शुभारंभ

जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से
तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर से 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ

वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश हैं या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंश पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचैनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादस्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझ लिया

गया और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके। मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचैतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचैतक प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधामोहन लाल अग्रवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सांसद अलका गुर्जर को स्थान नहीं मिला।

संगठन में लंबे अनुभव के साथ सक्रिय रहे हैं। जून 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक दायरा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पुनिया को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आने वाले समय में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियानों में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखना उनके राजनीतिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका को

लेकर पार्टी के भरोसे का संकेत माना जा रहा है। राजे इससे पहले जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उपाध्यक्ष थीं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान सहित, आदिवासी बहुल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में रावत की भूमिका अहम हो सकती है। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को पीपूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन नियुक्तियों के जरिए राजस्थान के संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को केन्द्रीय संगठन में जगह दी गई है। नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। इसके बजाय राजेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली शिफ्ट होंगे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनैतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सोमवार को नई दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात ने एक बार फिर उन्हें केन्द्र सरकार में लिए जाने की संभावना को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इनमें राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो विस्तार और नदी जोड़ो परियोजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने केन्द्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं के लिए केन्द्र से और अधिक सहयोग की भी मांग की। हालाँकि, बाद में उन्होंने दिल्ली

- फड़नवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल का प्रशासनिक अनुभव है, वे युवा हैं और उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है, यही नहीं, अक्सर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी के विकल्प के रूप में उनका नाम लिया जाता है, हालांकि, खुद फड़नवीस इससे इंकार कर चुके हैं।
- चर्चा है कि अगर फड़नवीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्हें संभवतया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।
- फड़नवीस ने कहा कि उनकी प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात राज्य की योजनाओं के संदर्भ में थी, वे दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे।

आने की अटकलों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में फड़णवीस ने कहा कि जो लोग ऐसी अटकलों के “गुब्बारे” या “पतंगें” उड़ा रहे हैं, वे

ऐसा करते रहें, लेकिन वे महाराष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फडणवीस को लेकर मौजूदा अटकलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर में रहने वाले भारतीय यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 अगस्ता कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रেমिटेंस)

- यह सेवा डाक विभाग तथा कतर डाक सहित संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक सहित, अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।
- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है। “दिमागी नक्सल” का तंत्र इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को रा्ट्र-

विरोधी या वैचारिक रूप से दृष्टित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

की यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनेरेशन ज़ी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी के जैनेरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मूल कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है। सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर एयरलाइन किराया बढ़ाये तो केन्द्र उड़ानें रोके’

नई दिल्ली, 17 अगस्ता उच्चतम न्यायालय ने त्योंहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ावों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सख्त निर्देश दिये।

अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने पान मसाला ब्रांड का प्रचार, कानून से खिलवाड़ की एक और मिसाल

महाराष्ट्र सरकार ने विमल इलायची के प्रचार के लिए बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एक्शन लेकर “सरोगेट एडवर्टिज़मेंट” के खेल को सुर्खियों में ला दिया है

- “सरोगेट” यानि छत्र विज्ञापन वे विज्ञापन हैं, जिनमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है, जैसे विमल गुटखा के प्रचार के लिए विमल इलायची का विज्ञापन किया जाता है।
- भारत में तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून रोक है और इस कानून में बाद में ऐसे नियम भी जोड़ दिए गए, जिनमें तंबाकू उत्पाद ब्रांड के प्रचार के लिए अन्य उत्पाद का प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून की गाइडलाइन्स में भी “सरोगेट” विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्मी हस्तियों पर की गई कार्यवाही सैलिब्रिटी विवाद बन कर न रह जाए, यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि, यह मुद्दा इस विवाद का समाधान कर सकता है कि क्या किसी वैध उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।

वाली कंपनियाँ इलायची, माउथ फ्रेशनर और अन्य उत्पादों जैसे ब्रांड एक्सटेंशन के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखती हैं,

जबकि उक्त उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पहले से ही एक

मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.पी.टी.ए.), 2003 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

इस कानून के तहत बाद में बनाए गए नियम अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर भी रोक लगाते हैं। इनमें तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल अन्य सामान

सेवाओं या कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना भी शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्यवस्था भी इसमें एक और स्तर जोड़ती है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की 2022 की गाइडलाइंस उन वस्तुओं और सेवाओं के सरोगेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती हैं, जिनके विज्ञापन पर पहले से प्रतिबंध या रोक है। फिर भी इन नियमों को लागू करना मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बचाव (डिफेंस) सीधा है: विज्ञापन पूरी तरह से वैध उत्पाद के लिए है। इस बचाव की अदालतों में परीक्षा हो चुकी है। विमल इलायची से जुड़े एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारश्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीजल प्रबंधन में नए कीर्तिमान
जल समृद्ध हो रहा राजस्थान₹91,000 करोड़ की लागत से
राम जल सेतु लिंक परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- 4.98 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- 17 जिलों को पेयजल-जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर

₹34,102 करोड़ की
यमुना जल परियोजना

शेखावाटी को वर्षों बाद जल

32 वर्षों का इंतजार पूरा

चूरु, सीकर, झुंझुनू - भरपूर पानी



राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर

गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी-तंत्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के लिए राशि ₹5500 करोड़

लाभान्वित जिले - हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरु, बीकानेर, फलौदी

जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा

ब्राह्मणी-राणा प्रताप सागर- बनास लिंक

680 एमसीएम जल बनास नदी में अपवर्तन लाभान्वित जिले भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं डीग

₹2,500 करोड़

की अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना से बांसवाड़ा के 338 गांवों में सिंचाई

देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खारी फीडर की जल संवहन क्षमता को दोगुना करने की लगभग ₹150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

₹7,355 करोड़ की

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं 1402 गांवों में पेयजल सुविधा

पाली एवं सिरौही में पेयजल आपूर्ति हेतु सेई एवं साबरमती बांधों का निर्माण कर जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागत ₹1,255.90 करोड़ है साथ ही, सेई बांध की टनल क्षमता बढ़ाने पर ₹65 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

माही बेसिन के अनास एवं सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम बांध, जयसमंद बांध के साथ साथ सोम-कमला-अंबा बांध के माध्यम से जवाई बांध एवं जालौर तक आपवर्तित करने का संकल्प लाभान्वित जिले: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर एवं जोधपुर

विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। –साने गुरुजी

क्या सत्ताधीशों का काम केवल विरोध को कुचलने का रह गया है?

दिनांक 13 अगस्त, 2026 को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बी सी आई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया कि हैदराबाद के विधि विश्वविद्यालय, NALSAR के 2026 बैच के छात्रों का पंजीयन किसी राज्य की बार कौंसिल में नहीं किया जाएगा। बिना बार कौंसिल में रेजिस्ट्रेशन के कोई विधि स्नातक किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि NALSAR के छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाने का विरोध किया था और कहा था कि वे उनके हाथों से डिग्री नहीं लेंगे। इसका कारण यह बताया गया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के छात्रों की अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। जब दिल्ली में पुलिस अत्याचार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उनके पास ये चींटियों देखने के लिए समय नहीं है। यह बयान युवाओं के प्रति उनकी असंवेदनशीलता दर्शाता था। उनके फैसले, युवाओं के हित के विपरीत रहे हैं। पाठकों के लिए यह जानना उचित होगा कि पारंपरिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को NALSAR के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की तरह बुलाया जाता रहा है।

बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार से विधायक का चुनाव लड़ा। बाद में 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के कारण इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया ये 2014 से लगातार बार काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं। मिश्रा के इस मननमाने और बेतुके आदेश की सब वक्तों, नेताओं, यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने भी कड़ी निंदा की। कॉन्ग्रेस जनता पार्टी, (सी जे पी) के नेताओं ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि वे मनन मिश्रा के सरकारी आवास और उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। तीव्र विरोध को देखते हुए मनन मिश्रा को दो घंटों में ही अपना वया आदेश वापस लेना पड़ा। उन्होंने बड़े भोलेपन से मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि वे युवाओं के भविष्य को किसी प्रकार से खराब नहीं करना चाहते हैं ।

मनन मिश्रा का यह आदेश तो केवल एक उदाहरण है, वास्तविकता तो यह है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने का कार्य कर रहा है। विरोध के प्रति इतनी असहिष्णुता पहले नहीं देखी गई। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी, संविधान द्वारा दी गई है । जहां, जिसको अवसर मिलता है वह विरोध को सहन नहीं कर पाता और उसके स्वर को कुचलने का प्रयास करने लगता है।

देश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में 15–20 साल से छात्र संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं। अपनी राजनीतिक विचारधारा को अभिव्यक्त करने का कोई मंच ही छात्रों को उपलब्ध नहीं है। केंद्र एवं राज्यों में सरकारों ने अपने कुलपति और अध्यक्ष सभी शिक्षण संस्थाओं में बिठा दिए, ताकि छात्रों को उनकी ही विचारधारा को मानने हेतु बाध्य किया जा सके। सरकार विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों को टारगेट करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है ।

हाल ही में कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने इस आंदोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और छात्रों को सलाह दी कि इसमें भाग न लें। यह धमकी तक दी गई कि यदि उन्होंने इसमें भाग लिया तो उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। एक विश्वविद्यालय ने तो यहां तक लिख दिया कि यदि उनके विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में भाग लेंगे तो, विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के संबंध पर विपरीत भाव पड सकता है। ऐसे आदेश निकालने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, जे एन यू, जामिया मिलिया, आई आई टी खड़की और मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों का कार्य स्वतंत्र सोच को विकसित करने का है अथवा उसे दबाने का? यदि विश्विद्यालय, सरकार विरोधी विचारधारा के स्वर को दबाने का काम करेंगे तो उन्हें विश्वविद्यालय कहना बेमानी होगा। विश्वविद्यालय छात्र संघों से निकले कई छात्र नेता, बाद में राष्ट्रीय राजनीति में आए और विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जैसे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रवि शंकर प्रसाद आदि आदि।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान में दी गई है, उसे ही किसी न किसी तरह से, हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह काम सरकारी विभागों के अधिकारी तो करते ही थे, अब तो उच्च शिक्षण संस्थान तक यही करने लगे हैं। कई बार तो लगता है कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के मुखिया के रूप में नियुक्त होने के

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम केवल वर्तमान भाजपा सरकार ही नहीं कर रही है । पूर्व में भी, हर सत्ताधारी दल ने अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने और कुचलने का ही काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपातकाल के रूप में 1975 में सामने आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था।

प्रतिबंध लगा दिया गया । आपात काल के बाद मार्च, 1977 में जब चुनाव हुए, तब जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती है और जो भी उसे दबाने का प्रयास करेगा, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनता ने इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सरकार को 1977 के चुनावों में बुरी तरह पराजित करके सत्ता से उखाड़ फेंका।

गत कुछ वर्षों से जिस प्रकार की असहिष्णुता, विचारों की भिन्नता के लिए और सत्ताधारी दल के मत से अलग मत रखने वालीयों के प्रति दिखाई जा रही है, उससे तो यही लगता है कि राजनैतिक दलों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इस भय के वातावरण के कारण सरकार के विरुद्ध मुंह खोलना, जोखिम भरा काम हो गया है। जिन विद्यार्थियों ने कॉन्ग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रदर्शन में भाग लिया, पुलिस द्वारा उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कार्यवाही की जा रही है।

आजकल तो विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर एवं शिक्षकों के पदों पर चयन हेतु, सत्ताधारी दल की विचारधारा वाला व्यक्ति होगा, अनिवार्य शर्त बन गई है। यहां तक कि निजी विश्वविद्यालय में भी यदि सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई आवाज उठा दें, तो वहां के मुखिया को उनके मालिकों के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जाती है।

मीडिया अपनी सही भूमिका तभी निभा सकता है जब वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे और निष्पक्ष रहे । कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि मीडिया अंग्रेजी की कहावत “ more loyal than the king” को सही सिद्ध करने में लगा है। यह मीडिया निष्पक्षता की सभी सीमाओं को लांघते हुए सत्ताधारी दल को खुश करने में लगा है। इस प्रकार के मीडिया को ‘गोदी मीडिया’ की संज्ञा दी गई है यानि सरकारी की गोद में बैठा मीडिया। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, सरकार के अधिकाधिक विज्ञापन उन्हें मिलते रहें और सरकार का पूर्ण संरक्षण उन्हें प्राप्त हो।

आज, यदि धरातल के वास्तविक समाचार लोगों तक पहुंच रहे हैं तो, वह केवल सोशल मीडिया की बलिते वरते हैं। कुछ साहसी पत्रकार, फील्ड में जाकर वास्तविकता उजागर करने का प्रयास करते हैं किंतु उनके लिए भी जोखिम बहुत बढी है । सरकार के किसी निर्णय और कार्रवाई का विरोध, उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, इसके अनेक उदाहरण गत कुछ वर्षों में देखने में आए हैं । कई चैनल बंद कर दिए गए या उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ के विरुद्ध ई डी, सी बी आई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ दिया गया है।

सरकार विरोधी रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार तक कर लिया गया । यूपी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में पानी और नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चों को दिखा दिया तो सरकार ने उस पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया। जिस पत्रकार ने हाथरस बलात्कार और हत्या कांड के सच को मीडिया में प्रसारित करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उसकी जमानत भी सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुई।

कोई शायर या कर्मेडियन ऐसी कोई बात सार्वजनिक मंच से कह दे जो सरकार को अपने विरोध में दिखाई दे तो उस पर कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होती। सरकार के इस काम में, दुर्भाग्य से, प्रशासन भी पूरी तरह सहयोग करने के लिए, हर गैर कानूनी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता है । उदाहरणार्थ, लद्दाख के जिला प्रशासन ने बिना पर्याप्त कारण के, सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्वोरिटी एक्ट में गिरफ्तार करके सात महीने के लिए जेल में डाल दिया था। बाद में, स्वयं गृह मंत्रालय को एन एच के अंतर्गत जारी आदेश को वापस लेना पड़ा । इससे, सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रमुख भूमिका है, वहीं, संविधान की शपथ लेने वाले नौकरशाहों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी उत्तनी ही भूमिका है । यदि वे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें तो सरकार, चाहेतु हुए भी असंवैधानिक तरीके नहीं अपना सकती है। बस, इसके लिए उनको स्वयं को दो ही बातों से मुक्त करना होगा – भय और लोभ। अधिकारी गण, सरकार के उचित –अनुचित सभी आदेशों का पालन केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें मनमाना पोस्टिंग मिल जाए या वह नेताओं के साथ मिलकर अनेकित रूप से धन कमा सकें, या फिर वे इतने कायर है कि उनके विरुद्ध प्रताड़ना की कार्यवाही से भय खाते हैं। यदि अधिकारी अपने विवेक से कानून सम्मत काम करते तो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्रों पर प्लेटेड गन का इस्तेमाल नहीं होता और बिहार में कोई सिपाही एके–47, प्रदर्शनकारियों पर नहीं तान देता।

ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठे, उसका पहला काम ही विरोध के स्वर को दबाने का हो जाता है। यह प्रवृत्ति अब शायद जनता के दबाव से कम होगी और अधिकांरीगण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। राजनेताओं को सबक सिखाने का काम तो जनता, केवल चुनाव के माध्यम से पांच साल में एक बार कर सकती है। राजनीतिज्ञों को यह बात समझती होगी कि जनता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करके वे न केवल लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे अपितु स्वयं की छवि और भविष्य को भी बेहतर बना पाएंगे। अन्यथा, मौका लगने पर जनता उन्हें कैसे पटखनी दे देती है, इसका इतिहास गवाह है ।

–अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र भागवान

(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मदन सिंह काला

संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू हुआ, तो हर भारतीय नागरिक से चार वादे किए – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 75 वर्ष बाद आज हमें यह परखना है कि इन वादों को जमीन पर उतारने में हम कहां तक सफल हुए। यदि प्रस्तावना एक संकल्प है, तो आरक्षण उस संकल्प को पूरा करने का सबसे बड़ा संवैधानिक उपकरण है।

इतिहास हमें बताता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बाहरी आक्रांता नहीं, बल्कि अंदर की फूट थी। इस फूट की जड़ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में थी। समाज को चार हिस्सों में बांट दिया गया। ब्राह्मण को समस्त समाज को शिक्षा देने का दायित्व मिला, पर उसने उसे सीमित रखा। क्षत्रय को रक्षा की जिम्मेदारी मिली, पर वह अकेला बार–बार हारता गया क्योंकि उसके पीछे पूरा समाज नहीं खड़ा था। वैश्य का काम शुद्ध व्यापार था, पर उसने उसे ईमानदारी से नहीं निभाया गया। शूद्रों को खेती, पशुपालन, भवन निर्माण, कपड़ा बुनाई, लोहे–सोने का काम, जूते बनाने जैसे सभी तकनीकि व उत्पादकता जैसे कार्यों में लगा दिया गया, लेकिन उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। अतिशूद्रों को तो “पूर्व जन्म के कर्मों” का हवाला देकर अछूत घोषित कर समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया।

इस तरह समाज की 80–85 प्रतिशत शक्ति को शिक्षा, सम्मान और

अवसरों से दूर रख दिया गया। नतीजा यह हुआ कि देश न आर्थिक रूप से मजबूत बन पाया, न सैन्य रूप से और न बौद्धिक रूप से। यही कारण है कि हम बार–बार गुलाम हुए।

इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने ‘सकारात्मक कार्रवाई’ का मार्ग चुना। यह कोई राजनीतिक चाल या दया नहीं थी, बल्कि एक संवैधानिक उपचार था। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संविधान में आरक्षण का आधार कभी आर्थिक कमजोरी नहीं रहा। संविधान सभी में बहस के दौरान डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्पष्ट कहा था – “I don't prefer the competent government, I prefer the representative government.” इसका अर्थ है आरक्षण का उद्देश्य ‘योग्य सरकार’ नहीं, बल्कि ‘प्रतिनिधि सरकार’ बनाना है। इसलिए अनुच्छेद 16(4) में आधार ‘सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन’ रखा गया है। दुनिया के अन्य देशों में भार Affirmative Action है, लेकिन उसका आधार भी आर्थिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव और कम प्रतिनिधित्व है।

–आरक्षण प्रतिभा के विरुद्ध व्यवस्था नहीं है; यह उस असमान प्रारंभिक स्थिति को संतुलित करने का संवैधानिक प्रयास है जिसमें सभी प्रतियोगियों को समान अवसर कागज पर तो मिलता है, लेकिन सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं।–जिस बच्चे के घर में किताब नहीं, कोचिंग नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, उसे उसी लाइन से दौड़ाना जहाँ दूसरे के पास पीढ़ियों से संसाधन हैं, यह समानता नहीं होगी। आरक्षण उसी दौड़ को बराबर करने के लिए ‘हैंडीकेप’ की तरह है। एक बार बराबरी आ जाए, फिर मैदान सबके लिए खुला है।

75 वर्षों का परिणाम सामने है। एससी/एसटी की साक्षरता 1951 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 70 प्रतिशत से अधिक हो गई। आज इन वर्गों से आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं। राज्यों में आरक्षण की स्थिति अलग–अलग है। खिक्कम में कुल 85 प्रतिशत आरक्षण है, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत, राजस्थान में 64 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत और कर्नाटक में 50 प्रतिशत की सीमा लागू है, जिसे राज्य सरकार ने 66 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र में एससी 15 प्रतिशत, एसटी 7.5 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत और इंडब्यूपएस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

आरक्षण के बाद भारत की तस्वीर बदली। आजादी के बाद हम कभी किसी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं बने। हमारी तीनों सेनाएं – थल, नौसेना, वायुसेना – दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हैं।–ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कॉम्बैट/लड़ाकू भर्ती में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है।–वहां चयन पूरी तरह मेरिट, शारीरिक दक्षता और राष्ट्र भक्ति के आधार पर होता है, और यही हमारी ताकत है। इसी तरह ओलंपिक और एशियाड में भी कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के खिलाड़ी मिलकर मेडल लाते हैं। यह सिद्ध करता है कि अवसर मिलने पर हर वर्ग प्रतिभा दिखा सकता है।

पिछले वर्षों में ‘समरसता’ शब्द भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। लेकिन यहां गंभीर आपत्ति है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्वयं कहा था – “I don't want Samrasta, I want Samata।” पूरे समरसता नहीं, समानता चाहिए। यदि ‘समरसता’ का अर्थ जन्म आधारित कर्म को स्वीकार करता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। संविधान का लक्ष्य ‘समरसता’ नहीं, बल्कि ‘समानता और बंधुत्व’ है। वास्तविक समरसता तभी होगी जब हर वर्ग का व्यक्ति मंदिर से लेकर प्रयोगशाला तक, खेत से लेकर संसद तक, अपनी योग्यता से आगे बढ़ सके।

सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के बाद भी समाज के कुछ क्षेत्रों में असमानता बिकराये को लेकर कई बार राजनेताओं और जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। अपनी समस्या से अवगत करवाया है और किराये को तर्कसंगत एवं सामान्य करने की मांग रखी है। लेकिन लगातार आग्रह के बावजूद यदि प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं होता तो आखिर ये अपनी बात किसके सामने रखें? सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं। टाउन हॉल भी जनता की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका उद्देश्य केवल किराये से अधिकतम राज्यस्व अर्जित करना नहीं हो सकता। व्यावसायिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन एक कैसे हो सकते हैं? जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा व्यावसायिक कार्यक्रम और गैर-व्यावसायिक सांस्कृतिक आयोजन एक समान नहीं होते।

यदि कोई बड़ा व्यावसायिक कार्यक्रम है, किसी कंपनी का प्रचारात्मक आयोजन है अथवा ऐसा कार्यक्रम है जिससे आयोजक को आर्थिक लाभ होता है, तो उसके लिए अलग किराया निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्थानीय रंगकर्मों जब अपनी जेब से या सीमित सद्योग से नाटक तैयार करते हैं, साहित्यकार साहित्यिक मोष्टी आयोजित करता है या कोई सामाजिक संस्था जनजागरूकता का कार्यक्रम करती है, तो उनसे उसी किराये को लेकर कई बार राजनेताओं और जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। अपनी समस्या से अवगत करवाया है और किराये को तर्कसंगत एवं सामान्य करने की मांग रखी है। लेकिन लगातार आग्रह के बावजूद यदि प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं होता तो आखिर ये अपनी बात किसके सामने रखें? सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं। टाउन हॉल भी जनता की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका उद्देश्य केवल किराये से अधिकतम राज्यस्व अर्जित करना नहीं हो सकता। व्यावसायिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन एक कैसे हो सकते हैं? जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा व्यावसायिक कार्यक्रम और गैर-व्यावसायिक सांस्कृतिक आयोजन एक समान नहीं होते।

यदि कोई बड़ा व्यावसायिक कार्यक्रम है, किसी कंपनी का प्रचारात्मक आयोजन है अथवा ऐसा कार्यक्रम है जिससे आयोजक को आर्थिक लाभ होता है, तो उसके लिए अलग किराया निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्थानीय रंगकर्मों जब अपनी जेब से या सीमित सद्योग से नाटक तैयार करते हैं, साहित्यकार साहित्यिक मोष्टी आयोजित करता है या कोई सामाजिक संस्था जनजागरूकता का कार्यक्रम करती है, तो उनसे उसी

दिखती है। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, के कई धार्मिक स्थलों, दुर्गों और पूजा से जुड़ी भूमिकाओं में आज भी पीढ़ीगत आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का वर्चस्व है। शूद्र और अतिशूद्र वर्ण की जातियों को व्यवस्थित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसी तरह देश के चार पीढ़ों के शंकराचार्यों और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों जैसे शीर्ष पदों परंपरागत रूप से जन्म के आधार पर ही चयन होता आया है। जब तक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में सभी वर्गों को समान सम्मान और भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ‘बंधुत्व’ अधूरा रहेगा।

इस संदर्भ में इंडब्यूपएस आरक्षण का प्रश्न भी उठता है। 10 प्रतिशत इंडब्यूपएस आरक्षण को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माना जा सकता है। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि यह एससी/एसटी और ओबीसी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर लागू ही नहीं होता यदि आधार आर्थिक है, तो फिर इन वर्गों के गरीबों को इससे बाहर क्यों रखा गया? इससे स्पष्ट है कि इसका आधार सामाजिक स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिना गहन बहस के स्वीकार कर लिया, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह प्रावधान संदिग्ध है।

अब समय आ गया है कि हम आरक्षण को अंतिम लक्ष्य न मानें। –आरक्षण अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि समान अवसर तक पहुंचने का साधन है। अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें जन्म व्यक्ति की शिक्षा, सम्मान, रोजगार, नेतृत्व और जीवन की संभावनाओं को निर्धारित न करे। इसके लिए हमें एक संयुक्त मॉडल अपनाना होगा – आरक्षण + गुणवत्तापूर्ण शिक्षा + आर्थिक सशक्तिकरण + सामाजिक प्रतिनिधित्व + संवैधानिक बंधुत्व।

इसके लिए सबसे पहले हर 10 वर्ष में सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि नीति सही आंकड़ों पर बने और ओबीसी के लिए ‘क्रीमी लेयर’ को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा बड़ा कदम शिक्षा में होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता,

–मदन सिंह काला, पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

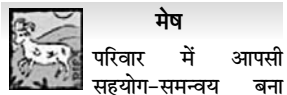
रंगमंच महंगा होगा तो अभिव्यक्ति सस्ती कैसे रहेगी?

दर पर किराया लेना न्यायसंगत नहीं है।

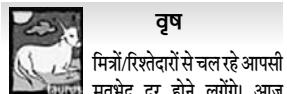
सरकार को चाहिए कि टाउन हॉल के किराये की अलग–अलग श्रेणियाँ निर्धारित करे। व्यावसायिक आयोजनों के लिए सामान्य दर हो, जबकि साहित्य, कला, रंगमंच, लोक संस्कृति, विद्यार्थी गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े गैर–व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अत्यंत रियायती दर रखी जाए। बीकानेर के रंगकर्मियों ने रवींद्र रंगमंच के लिए एक–दो वर्ष नहीं, बल्कि लगभग तीन दशक तक संघर्ष किया। अंतोद्वार किए, आवाज उठाई और सरकारों के सामने अपनी मांग रखी। लंबे संघर्ष के बाद रवींद्र रंगमंच बना। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसका किराया भी सामान्य रंगकर्मों की आर्थिक पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में जिस मंच के लिए कलाकारों ने वर्षों संघर्ष किया, वही मंच यदि कलाकारों के लिए महंगा हो जाए तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। फिर भी टाउन हॉल की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लंबे समय से बीकानेर की सांस्कृतिक गतिविधियों का सुलभ केंद्र रहा है। यदि टाउन हॉल भी कलाकारों की आर्थिक पहुंच से बाहर हो गया तो छोटे रंगकर्मियों और साहित्यिक–सांस्कृतिक संस्थाओं के पास आखिर कौन–सा विकल्प बचेगा?

सरकारें बड़े–बड़े सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करती हैं। मंच सजते हैं, कलाकार बुलाए जाते हैं और संस्कृति के संरक्षण की बातें होती हैं। लेकिन संस्कृति का वास्तविक संरक्षण तब होगा, जब स्थानीय कलाकारों को वर्षभर मंच उपलब्ध होगा। बीकानेर के कलाकारों को किसी बड़े महोत्सव में

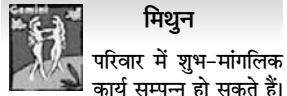
–राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद– साहित्यकार



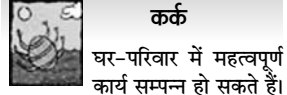
परिवार में आपसी सहयोग–सम्बन्ध बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार के धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।



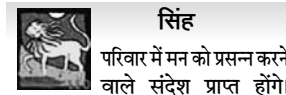
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगे। आज अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों एवं व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



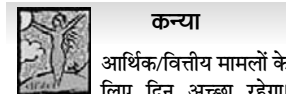
परिवार में शुभ–मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



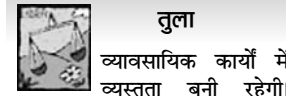
घर–परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आमगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।



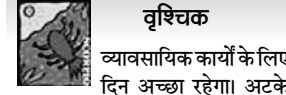
परिवार में मन को प्रसन करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।



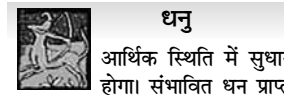
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



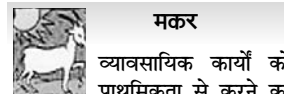
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकेगी है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



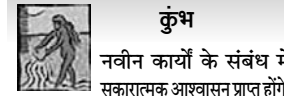
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।



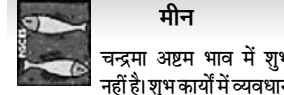
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर–परिवार में अतिथियों का आमगम हो सकता है।



व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य बनने लगेगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।



नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशयस प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



चंद्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विचयन हो सकता है। आज व्यक्तित्व पारिवारिक कार्यों के करण मानसिक तनाव रहेगा।

बीकानेर नगर निगम चुनाव वार्डों का आरक्षण तय, अब दावेदारों की नजर टिकट पर

बीकानेर, (कासं)।नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर बीकानेर में वार्ड आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से 17 अगस्त को नगर निगम के 80 वार्डों के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण तय होने के साथ ही पार्षद पद के दावेदारों की चुनावी तैयारियों को भी नई दिशा मिल गई है। जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन में हुई प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया। बीकानेर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। नगर निगम के 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनका निर्धारण 2011 की जगनगाम में वार्डवार अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर किया गया है। सबसे अधिक आबादी वाले वार्ड को प्राथमिकता देते हुए घटते क्रम में 9 वार्ड चिन्हित किए गए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में वार्ड 9, 77, 71, 33, 4, 45, 48, 16 और 5 शामिल हैं।

इनमें वार्ड 9 में अनुसूचित जाति की आबादी 65.98 प्रतिशत है, जो सभी वार्डों में सर्वाधिक है। इसके बाद

वार्ड 77 में 40.14 प्रतिशत, वार्ड 71 में 37.50 प्रतिशत और वार्ड 33 में 36.19 प्रतिशत एससी आबादी दर्ज की गई है। आरक्षण के लिए चिन्हित वार्डों में वार्ड 9 सबसे ऊपर रहा। यहां कुल 8433 की आबादी में 5564 लोग अनुसूचित जाति वर्ग से हैं।

इसके बाद वार्ड 77 में 7538 की कुल आबादी में 3026 एससी आबादी है। वार्ड 71 में 8767 में से 3288 और वार्ड 33 में 8015 में से 2901 आबादी अनुसूचित जाति की है। नगर निगम के बाकी वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और महिला आरक्षण का निर्धारण भी किया गया है। उपलब्ध आरक्षण विवरण के अनुसार नगर निगम में 16 वार्ड तथा सामान्य वर्ग के 55 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। संबंधित श्रेणियों में महिला आरक्षण भी लागू किया गया है।

इस आरक्षण के बाद कई वार्डों में लम्बे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों का समीकरण बदल गया है। अब दावेदार अपने वार्ड की नई आरक्षण श्रेणी के अनुसार चुनावी रणनीति बनाने में जुटेंगे। जिला प्रशासन के कार्यवाही प्रतिवेदन के अनुसार नगर निगम बीकानेर के सभी 80 वार्ड पुनर्गठन और पुनर्सिमांकन

- बीकानेर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। नगर निगम के 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 16 वार्ड अन्य तथा सामान्य वर्ग के 55 वार्ड निर्धारित किए गए हैं**

की प्रक्रिया ख्मे शामिल किए गए हैं। वार्डों की आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन होने के कारण सभी वर्गों में आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से संपादित की गई। राजस्थान में 17 अगस्त को विभिन्न नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई, जिससे आगामी निकाय चुनावों के लिए वार्डवार चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो रही है।

बीकानेर नगर निगम सहित नोखा, श्रीदुंगरगढ़, कोलायत, नापासर, लूणकरनसर और खाजुवाला नगर पालिका क्षेत्रों के पार्षदों के आरक्षेण के लिए लॉटरी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन और मौजूदगी के

निकाली गई। इस दौरान श्रीदुंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, बीकानेर पश्चिम विधायकजेठानंद व्यास, श्याम पंचारिया, श्रीमती सुमन छाजेड़, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, मदन मेघवाल, प्रहलाद मार्शल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनु ने लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी दी। दो नन्हीं बच्चियों परिधि और युवानी पडिहार ने यह लॉटरी निकाली।

11 निकायों के 345 वार्डों का आरक्षण तय : श्रीगंगानगर जिले के 11 निकायों के कुल 345 वार्डों की आरक्षण स्थिति साफ हो गई है। इनमें एससी के 96, एसटी के 6 और ओबीसी के 55 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जबकि 188 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। आरक्षण में एसटी महिला के 32 और ओबीसी महिला के 18 वार्ड शामिल हैं। जबकि एसटी में महिला के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है। वहीं अनारक्षित वर्ग में 60 वार्ड महिलाओं के लिए रखे गए हैं। यानी जिले के 11 निकायों में कुल 110 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं।

इनमें श्रीगंगानगर नगर परिषद के 65, सूरतगढ़ के 45, रायसिंहनगर के

लटके बिजली तारों के करंट से ऊंट घायल

पुगल, (कासं)।पुगल क्षेत्र के 14 एडी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। सोमवार दोपहर को गांव में बिजली के खंभों पर लटके ढीले तारों की चपेट में आने से एक ऊंट को करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति गहरा रोष है।

गांव के तीर्थ सिंह सोढ़ा, महेश सिंह सोढ़ा, सरूप सिंह, भगवान सिंह भाटी और किशन सिंह सोढ़ा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई स्थानों पर बिजली के तार लम्बे समय से ढीले होकर लटक रहे हैं। इन ढीले तारों के कारण पशुओं के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए भी हादसे का खतरा बना हुआ है।

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। इसके बावजूद ढीले तारों को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते विद्युत लाइनों को दुरुस्त नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

पौधारोपण से पुष्करणा दिवस का आगाज

बीकानेर, (कासं)। द पुष्करणाज फाउंडेशन के द्वारा सोमवार को कार्यालय में पुष्करणा दिवस को लेकर हुई बैठक में पुष्करणा दिवस के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया।

पुष्करणाज फाउंडेशन के मोहित पुरोहित ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता जिसका शीर्षक कला एवं संस्कृति व खेल और संस्था का समाज के प्रति दायित्व रहेगा। साथ ही वृक्षारोपण (खेजड़ी) और खेल सेमिनार के साथ शिक्षाविद और पंच परमेश्वर एवं बीकानेर प्रवासी का सम्मान एवं कला संस्कृति खेल सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 24 अगस्त को पुष्करणा दिवस कार्यक्रम का आगाज वृक्षारोपण अभियान से किया जायेगा जो कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के पास 1 कोस वाली प्वाक शिव मंदिर के पास पौधारोपण किया जायेगा।

35, गजसिंहपुर के 20, केसरीसिंहपुर के 20, श्रीकरणपुर के 25, अनूपगढ़ के 35, श्रीविजयनगर के 25, सादुलशहर के 25, पदमपुर के 25 और घड़साना के 25 वार्ड शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11–11 वार्ड श्रीगंगानगर और रायसिंहनगर में, जबकि 1–1 वार्ड वाले 6 निकाय हैं। श्रीगंगानगर निकायों और जिला परिषद प्रमुखों की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली गई। इस बार श्रीगंगानगर में मेयर पद आरक्षित नहीं रखा गया है। यानी किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर बन सकता है। लॉटरी की शुरुआत श्रीगंगानगर नगर परिषद के वार्डों से हुई।

कलेक्टर डॉ. अमित यादव, एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों से भाजपा के मधुसूदन बिहाणी और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाल राय टाक भी मौजूद थे।

लॉटरी के शुरुआती दौर में ही दिग्गजों की विकटें गिरनी शुरू हो गई। जैसे-जैसे विकटें गिरती रही, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगीं। अब ये नेता दूसरे वार्डों में जाकर पार्टी टिकट हासिल करने या निर्दलीय रूप से मैदान में उतरने की रणनीति पर काम करेंगे।

दो महीने से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर, (कासं)। जिले के जसरासर थाना पुलिस ने युवक की मौत के मामले में 2 महीने 10 दिन से फरार चल रहे आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर युवक की धोखे से बुलाकर बांधने और लाठी, सरिए व बेल्ट से मारपीट करने का आरोप है। गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस ने राजेश को थाना स्तर पर टॉप–10 बांछित अपराधियों में चिन्हित कर रखा था। आरोपी से अब घटना में उसकी भूमिका और फरारी के दौरान ठिकानों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार 6 जून 2026 को जसरासर निवासी राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके बेटे को

महिला टीचर के घर से लाखों के जेवर चोरी

नोखा, (कासं)। नोखा में एक सरकारी महिला टीचर के घर से लाखों रूपए के सोने–चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गई। चोरों ने आलमारी का लॉकर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब शिक्षिका ने अपनी आलमारी खोली तो पता चला।

घटद् निवासी शारदा बिश्नोई ने नोखा थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह सरकारी शिक्षिका हैं और पिछले तीन वर्षों से जोरावरपुरा स्कूल के पास नोखा मंडी में किराये के मकान में रहती हैं। उनका एक पुत्र राजवीर नोखा में पढ़ाई करता है। शारदा बिश्नोई के अनुसार वह स्कूल जाते समय अपने मकान की चाबी पोच में रखती थी। क्योंकि उनका पुत्र राजवीर स्कूल से उनसे पहले घर आता है। सुबह करीब 6 बजे जब वह तैयार के लिए अपनी आलमारी खोली तो देखा कि आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था।

शक होने पर आलमारी में अपना सामान संपाला। जांच करने पर पता चला कि आलमारी से करीब साढ़े तीन भरी का एक सोने का मादलिया सेट, एक भरी का सोने का झुमरा सेट, एक कानों की सोने की लटकन सेट, दो सोने की बिंदी, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी कानों के लूंग, दो जोड़ी चांदी की पायजेब और करीब तीस हजार रूपए नकद गायब थे।

एक युवक को धोखे से बुलाकर लाठी-सरिए से पीटा था, इलाज के दौरान मौत हो गई थी

धोखे से बुलाया और बांधकर लाठी, सरिए व बेल्ट से मारपीट की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज होने के बाद जसरासर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है।

‘लाभार्थी को पीएम आवास निर्माण की किश्तें समय पर मिलें’

बीकानेर, (कासं)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कार्यशाला का आयोजन सोमवार को पंचायत समिति सभागार में हुआ। समारोह में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी शैलजा पांडे तथा श्याम पंचारिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के दस लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों की चाबी सौंपी गई। वहीं पंचायत समिति परिसर में बनने वाले प्रोपेटाइप आवास का शिलान्यास किया गया। श्याम पंचारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ निजी लाभ के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। आज गांव–गांव विकास के पथ पर बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ दिया जाए। प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण की किश्तें निर्धारित समय पर मिलें। वीबी–जीराम के तहत 90 दिन का रोजगार और पात्र लाभार्थियों को शौचालय की राशि भी समय पर दी जाए। विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया। इस दौरान अधिशाषी अभियंता रामेश्वर बेनीवाल, दिलीप सिंह आडसर सहित विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण भी किया।

सेंगाल धोरा में मेला भरा, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा

कक्कु, (कासं)। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को कक्कु क्षेत्र के प्रसिद्ध सेंगाल धोरा में विशाल मेला लगा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। पीठाधीश्वर परमेश्वर गिरि ने बताया कि मान्यता है कि सतयुग में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित मनकाेश्वर महादेव श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव का श्रद्धालुओं ने दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से अभिषेक कर सुख–समृद्धि की कामना की। श्रीकोलायत से कांवड़ लेकर एक पदयात्रा संघ सेंगाल धोरा पहुंचा। इन कांवड़ियों ने कपिल सरोवर से जल भरकर बोल बम और हर–हर महादेव के जयघोष के साथ मनकाेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में वेदपाठी पंडितों और बटुओं ने गंगाजल से रूद्राभिषेक किया और 1००8 बिल्वपत्रों से सहस्रार्चन पूजन संपन्न किया। बड़ी संख्या में शिवभक्त सेंगाल धोरा में वन भोजन के लिए भी पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाया और अपने परिवार के साथ प्राकृतिक वातावरण में वनभोजन का आनंद लिया। मेले में प्रसादी, फल और खिलौनों सहित विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी थीं। दिनभर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही। इस अवसर पर कक्कु के पूर्व सरपंच रेवन्त राम राहड़, पंचायत समिति प्रतिनिधि हिम्मताराम राहड़, पांच सरपंच रामचंद्र सियाग सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नक्षत्र पार्क में कैलाश पर्वत-नवग्रह निर्माण का भूमि पूजन

सूरतगढ़, (कासं)। यहां प्रसिद्ध श्रीहनुमान खेजड़ी मंदिर धाम स्थित नक्षत्र पार्क में सोमवार को कैलाश पर्वत और नवग्रह निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजा–अर्चना कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर श्रीहनुमान खेजड़ी प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और सेवादारों ने भाग लिया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र राठी, महासचिव मदन ओझा, उपाध्यक्ष रतन लाल सोनी व सुशील गुप्ता, सचिव श्रीकांत सारस्वत और कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद वसिष्ठ सहित कई सेवादार उपस्थित रहे। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा ने पंडित शंकर लाल शर्मा, पंडित कमल शर्मा और पंडित राजपाल शर्मा के साथ मिलकर विधिवत पूजा संपन्न कराई।

सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर में सरकारी स्कूलों में मीडिया के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जायेगी। स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही रजिस्टर में एंट्री करना भी अनिवार्य किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रिंसिपल और संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश को अनुमति नहीं होगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत को राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक ०1.09.2026 को 15.00 बजे तक खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं:- निविदा संख्या: 139। कार्य का नाम व स्थान: सारयाक मंडल इंजीनियर, हनुमानगढ़– द्वितीय के अधीन रायसिंहनगर में दो लिफ्ट (लेटकार्म नं. 1 व 2 पर) के प्राक्कान के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग कार्य करना। अद्वानुमित लागत मूल्य: Rs. 4623964.62। घरोहर राशि: Rs. 92500.00। नोट:- अन्य शर्तें रेलवे की वेब साइट www.irops.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
1196-MG-26
से ई ई ई NWR Railways NWR Railways , पर फ़ॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
वरिे मंडल बिजली इंजीनियर / टीआरबी, उ. प. रेलवे बीकानेर, भारत को राष्ट्रपति के वारंते व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित करते हैं। 1. सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता: http://www.irops.gov.in। 2. ई–निविदाएं बंद होने की तिथि व समय: 09.09.2026 को 15:00 बजे तक। 3. ई–निविदाएं खोलने की तिथि व समय: 09.09.2026 को 15:00 बजे के बाद। Tender Notice No. 02-TRD-BKN-E-TEAR-2026-27. Name of work: TRD modification work in c/w Provision of New TMC sidings along with facilities - 29 TMC overs along Bikaner Division. Approx Cost of the work: 3,80,51,116.00. EMD/SD (Rupees): 7,61,100.00. 1195-MG/26
से ई ई ई NWR Railways NWR Railways , पर फ़ॉलो करें

पटवारी ने स्कूल को वाटर कूलर भेंट किया

सूरतगढ़, (कासं)। सूरतगढ़ उपखंड के घमण्डिया क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजस्व पटवारी सोनू सहारण ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए करीब 85 हजार रूपए की लागत का वाटर कूलर और फर्नीचर भेंट किया।

सोमवार को किए गए इस सहयोग से स्कूल में अध्ययनरत करीब 3०० विद्यार्थियों को अब शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 11 मेज और स्टूल मिलने से विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था भी बेहतर होगी। स्कूल के प्रिंसिपल स्वर्ण सिंह बजरोत ने बताया कि पटवारी सोनू सहारण को इस पुनीत कार्य के लिए पंचायत शिक्षक संतकुमार गोदारा और राजेन्द्र पुनिया ने प्रेरित किया।

अनशनकारी छात्रों की तबीयत बिगड़ी

बीकानेर, (कासं)। छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा के नेतृत्व में चल रहा आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा।

अनशन के दौरान श्रीकृष्ण गोदारा सहित उनके साथी अभिमन्यु जाखड़, रामनिवास चौधरी और सोनू जोशी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बावजूद उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए अस्पताल में भी अनशन जारी रखा। लेकिन देर रात्रि को नोखा विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी और देहात अध्यक्ष विशनायाम सियाग ने डॉक्टरों की सलाह के बाद आंदोलनकारियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ती देख अस्पताल में भर्ती श्रीकृष्ण गोदारा सहित भर्ती आंदोलनकारियों को ज्यूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। लेकिन चारों

- छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग, अस्पताल में भर्ती आंदोलनकारियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अनशन खत्म कराया**

छात्रनेता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस देहात अध्यक्ष विशनाराम सियाग ने भाजपा सरकार पर छात्रों की मांगों को लेकर हठधर्मिता बरतने के लोकतांत्रिक अधिकारों की इस लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके संघर्ष में हरसंभव सहयोग किया जायेगा और

मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने,



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कृषि लागत कम करने और ऊर्ध्व आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का

शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नितिन नबीन ... आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली

के जरिए समन्वित बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया। इसमें 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई

समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

■ सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कार्यवाही कर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम किये

■ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमादा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

कतर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से पन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए सत्र के सफल संचालन में सहयोग करेंगे।

“दिमागी नक्सल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर खुद को संगठित किया है। स्पष्ट रूप से, मोदी का यह संदेश वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज की आवाजों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है, जिन्हें भाजपा लंबे समय से “अर्बन नक्सल” कहती रही है।

इसमें असहमति, विशेषकर शासन, शिक्षा व्यवस्था की निफलताओं या हिंदुत्व की प्राथमिकताओं की आलोचना, को वैध राजनीतिक विरोध के बजाय माओवादी विद्रोह के वैचारिक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस टिप्पणी को हताशा का पक्का संकेत बताया।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

■ मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की

■ मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।

छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दावाियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, परीक्षा में सफल अर्थार्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, "हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?"

जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

■ नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।

पुंरदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रती सिंह बादल, लाल सिंह अग्र, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा, मंगलाल रावत को अनुसूचित जनजाति और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अनिल बल्लू को फिर मीडिया संयोजक बनाया गया है। आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक बनाया गया है। दीपक म्हरके को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को सिंह, मुर्गाका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, जय प्रकाश को सौंपा गया है। वहीं, तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और महेन्द्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। डॉ. संवित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा को बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ के सह संयोजक ऋतुराज और विष्णु वर्धन रेड्डी को बनाया गया है।

राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, संदीप पाटक, फांमोनो कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, एम वेंकटेशन , राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अक्सर अपने आलोचकों को बदनाम करती है और बातें उन्हीं की मांगों को अपना लेती है। उन्होंने इसके उदाहरण के रूप में जातीय जनगणना का हवाला दिया।

विपक्ष के अन्य नेताओं, जिनमें भाकपा के डी. राजा भी शामिल हैं, ने इस शब्द को असहमति को दर्शाते कर्त्ताकृत करने और सरकार को सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बतायी है।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनावी के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाईस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

पारदर्शी मानदंड और कड़े डंड का प्रावधान हो। विज्ञापन एजेंसियों और सेलिब्रिटीज से भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं की ब्रांड पहचान वाले उत्पादों का विज्ञापन करने से पहले पूरी जाँच-पड़ताल करें। इस तरह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस सिर्फ एक और सेलिब्रिटी विवाद बनकर न रह जाएं। वे एक ऐसे सवाल को सुझावें का मौका दे सकते हैं जो बरसों से बना हुआ है: कोई उत्पाद कानूनी हो सकता है, लेकिन क्या उसका विज्ञापन कानूनी तौर पर किसी ऐसी चीज के विज्ञापन के रूप में काम कर सकता है, जो खुद कानूनी नहीं है?

जब तक इस सवाल का जवाब एक स्पष्ट रेगुलेटरी टेस्ट के जरिए नहीं दिया जाता, तब तक सरोटेट विज्ञापन की यह कानूनी खामी प्रतिबंधित ब्रांडों को बाज़ार में अपनी पहचान बनाए रखने का मौका देती रहेगी और उन्हें अपने उत्पाद को खुलेपन विज्ञापन करने की जरूरत भी पड़ेगी।

दिखाई दें, वहाँ विज्ञापन देने वाले पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ब्रांड विस्तार वास्तव में एक वास्तविक और स्वतंत्र कारोबार है। सेलिब्रिटी के विज्ञापन में शामिल होने की भी विशेष रूप से जाँच होनी चाहिए। कोई एक्टर यह तर्क दे सकता है कि उसने इलायची का विज्ञापन किया, तंबाकू का नहीं। लेकिन अगर विज्ञापन का मुख्य मकसद प्रतिबंधित तंबाकू ब्रांड की पहचान को लाखों उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है, तो इस अंतर को सही ठहराना लगातार मुश्किल हो जाता है।

उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वैध कारोबारों को कानूनी उत्पादों का विज्ञापन करने से रोका जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी कानूनी उत्पाद को गैर-कानूनी उत्पाद के विज्ञापन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनने से रोका जाए।

इसलिए भारत को ब्रांड विस्तार के लिए एक अधिक स्पष्ट और तकनीक से स्वतंत्र नियम की जरूरत है, जिसमें